(c) and (d) It is true that in States of Haryana, Kerala, Manipur, Punjab, Tripura and Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, Pondicherry and Delhi, very little surplus ceiling land is now available for distribution to landless as the land not yet been distributed is either locked in litigation or cannot be distributed due to other reasons.

States have been advised to plug loopholes in the ceiling laws and tighten their implementation in order to have more land available for distribution. Various steps have been suggested to them for expeditious disposal of pending ceilling cases including setting up tribunals under Article 323-B of the Constitution, and constitution of separate benches for ceiling cases in High Courts. The consensus of Revenue Ministers Conferences on various aspects of land reforms implementation has also been conveyed to these States for necessary action. Land being a State subject, the responsibility to act upon these suggestions rests with the State Government.

Uniform labour laws in South Asian Region

1805. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the South Asian Regional Trade Union Council (SARTUC) has demanded to various Governments in the region to have a dialogue with trade union representatives on the uniformity of labour laws from the trade union point of view;

(b) if so, whether Government propose to examine the demand of the SARTUC and also propose to bring forward uniform labour laws; and

(c) if so, full details in this regard?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) No memorandum has been received by the Government in this regard.

(b) and (c) Do not arise.

बिना बारी के भूखण्डों का आवंटन

1806. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने चालू वर्ष में 1 जनवरी, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान अनेक आवासीय, औद्योगिक और व्यापारिक भूखंडों और मकानों का बिना पारी के आवंटन किया है ; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा ऐसे आवंटन के क्या कारण है; और

(ख) क्या ऐसे आवंटनों के लिए कतिपय लोगों द्वारा सिफारिश की गई थी यदि हां, तो उन आवंटनों की कुल संख्या क्या है जो बिना किसी सिफारिश के किए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1 जनवरी, 1988 से 30 सितम्बर 1988 तक की अवधि के दौरान रिहायशी, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्लाटों का बिना बारी का कोई आवंटन नहीं किया गया है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता है।

फसल बीमा योजना को पुनः आरम्भ किया जाना

1807. **श्री राम जेठमलानी :**
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने लम्बित पड़ी फसल बीमा योजना को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि योजना आयोग द्वारा उठायी गयी कतिपय आशंकाओं को दूर कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस योजना को अविलम्ब लागू न किए जाने के क्या